

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला-श्रीगंगानगर

रणजीत बनाम शंकरलाल आदि

किस्म मुकदमा:-88 आर0टी0ए0

प्रकरण संख्या:-250 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.01.2024	<p>वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य हैं तथा परस्पर सहदायिकी एवं सहअंशदायी हैं। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से एकल खाता की खातेदारी कृषि भूमि वाके तहसील सूरतगढ़ के चक 11 एसपीडी-बी के खाता सं. 43 के प.नं. 207/13 के किला नं. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 12/1, 13 ता 17, 18/1, 19/1, 23/1, 24, 25, प.नं. 207/21 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/3, 2/4, 9 ता 11, 12/1, 12/2, 22 कुल तादादी 5.554 है.क. मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वाद पत्र की दफा 3 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि पूर्व में वादी के दादा श्री रामचन्द्र के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी जिनके देहान्त के पश्चात उक्त कृषि भूमि उनके वारिसों को ओद हुई। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित हो चुका है अर्सा दराज पूर्व वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक सदस्यों ने प्रश्नगत कृषि भूमि का अच्छी मंदा व काशत की सहुलियत के हिसाब से घरा घरू बंटवारा करवा दिया और घरू बंटवारा के समय वादी व प्रतिवादी सं. 1-2 प्रत्येक को 1/3-1/3-1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ और इसी अनुसार वादी व प्रतिवादी सं. 1-2 काबिज काशत हुए। वादी का कब्जा वाद पत्र की दफा 3 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा पर कब्जा घरू बंटवारा के समय ही बिना किसी वाद विवाद के चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी वादी ने फसल काशत की हुई है लेकिन वर्तमान राजस्व राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज होने से वादी की हकूक खातेदारी पर विपरित असर पड़ता है। इसलिए वादी वाद पत्र की दफा 3 में प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि में से 1/3 हिस्सा कृषि भूमि की घोषणा करवाने का अधिकारी हैं। वादी ने प्रतिवादीगण से कई दफा कहा कि वे वादी का घोषणा करवाने एवं कब्जा काशत की कृषि भूमि की घोषणा करवा देवे तो मुताबिक घरू बंटवारा एवं कब्जा काशत की कृषि भूमि की घोषणा करवा देवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो टालमटोल करते रहे, परन्तु आज से 5 दिवस पूर्व प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया है, बस यही वाद हेतूक है। वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे।</p> <p>वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होने के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़ने समझने के बाद हस्ताक्षर किये। वादी की पहचान श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री अमरजीत सिंह अधिवक्ता द्वारा किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।</p> <p>वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण में दोनो पक्ष एक ही परिवार के सदस्यगण हैं। दोनो पक्षों द्वारा कुछ दिन पूर्व किये गये पारितवारिक समझौते अनुसार व परिवार के प्रमुख रिश्तेदारों के प्रोत्साहन से परस्पर मुकदमेबाजी नहीं होने के लिए स्वेच्छा पूर्ण लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि वाके चक 11 एसपीडी-बी के खाता सं. 43 के प.नं. 207/13 के किला नं. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 12/1, 13 ता 17, 18/1, 19/1, 23/1, 24, 25, प.नं. 207/21 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/3, 2/4, 9 ता 11, 12/1, 12/2, 22 कुल तादादी 5.554 है.क. में वादी व प्रतिवादी सं. 2 प्रत्येक को 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक कृषि भूमि है। प्रथम पक्ष / वादी का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तो पक्षकारान को कोई उजर एतराज नहीं होगा। राजीनामा पक्षकारान ने अपनी सहमति से किया है जिसे पक्षकारान ने पढ़, सुन समझ तथा पूर्ण रूप से समझ में आ जाने के बाद सही होना माना। लिहाजा राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण/ प्रथम पक्ष का वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जावे।</p> <p>प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होने पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होने के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होने से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों ने वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करने हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40-53, 38-39-40, आर.आर.डी., 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178</p>	



उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

03.01.2024

आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975-478, ए.आई.आर. 1966 (एससी) 432 आर.आर. डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (गुप-6) विभाग जयपुर के पत्रांक प. 5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमति हो जाये तो ऐसी सहमति के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकारी विधि के अनुसार पुत्र को अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिए पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है। ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौते पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो। मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221-22 के अनुसार संयुक्त परिवार की सम्पत्ति पर भी पुत्र पुत्रीयों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दु परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पत्ति को संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपने कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी) डी.एन.जे. (एससी) पेज 2023 पेज 29, आर.आर.डी. 1998 पेज 644, आर.आर.डी. 1995 पेज 529 पेश किये।

हमने वादी एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित कृषि भूमि वाके चक 11 एसपीडी-बी के खाता सं. 43 के प.नं. 207/13 के किला नं. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 12/1, 13 ता 17, 18/1, 19/1, 23/1, 24, 25, प.नं. 207/21 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/3, 2/4, 9 ता 11, 12/1, 12/2, 22 कुल तादादी 5.554 हैक्. जो प्रतिवादी सं. 1 के नाम से दर्ज राजस्व अभिलेख खातेदार भूमि है जो जाददी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

**-:: आदेश ::-**

वादी एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित भूमि चक 11 एसपीडी-बी के खाता सं. 43 के प.नं. 207/13 के किला नं. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 12/1, 13 ता 17, 18/1, 19/1, 23/1, 24, 25, प.नं. 207/21 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/3, 2/4, 9 ता 11, 12/1, 12/2, 22 कुल तादादी 5.554 हैक्. में से वादी को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड़ पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 03.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)**



(ओ021 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

--:परचा डिक्री:--

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर  
(बइजलास :-सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.)

--: अनवान ::--

1.रणजीत पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन 11 एसपीडी-बी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

-वादीया

बनाम

1.शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन 11 एसपीडी-बी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

2.मनोज कुमार पुत्र शंकरलाल जाति जाट साकिन 11 एसपीडी-बी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा-88 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 250 वर्ष 2023 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री हीरालाल बिस्थलिया व वकील प्रतिवादीगण श्री अमरजीत सिंह संधू के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:-

वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे प्रतिवादी सं. 1 के नाम वर्णित भूमि चक 11 एसपीडी-बी के खाता सं. 43 के प.नं. 207/13 के किला नं. 1/1, 1/3, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 9, 10/1, 12/1, 13 ता 17, 18/1, 19/1, 23/1, 24, 25, प.नं. 207/21 के किला नं. 1/1, 1/2, 2/3, 2/4, 9 ता 11, 12/1, 12/2, 22 कुल तादादी 5.554 हैक्. मे से वादी को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होंने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होंने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होंने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होंने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे।

नोज.....ग.....मुबलिंग.....ग.....बाबत.....ग.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....ग..... फस्दों की पालना.....ग.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 03.01.2024 को जारी की गई।



(सन्दीप कुमार)

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)